Indian J. Soc. & Pol. 12 (02):95-98: 2025 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JULY 2025 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

जो बाइडेन प्रशासन के दौरान हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में अमेरिका–भारत संबंध : चीन के लिए निहितार्थ

गिरीश चन्द्र पाण्डेय[1], रचना कुशवाहा[2]

[1]आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी देवानन्द पी.जी.कालेज, मठलार, देवरिया उत्तर प्रदेश, भारत
[2]शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

ABSTRACT

हिंद–प्रशांत क्षेत्र आज वैश्विक भू–राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है, जहां भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी चीन की बढ़ती आक्रामकता और प्रभाव का संतुलित प्रत्युत्तर दे रहे हैं। बाइडन प्रशासन के दौरान यह द्विपक्षीय सहयोग BEC, COMCASA जैसे रक्षा समझौतों और क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ हुआ। इस साझेदारी का उद्देश्य एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद–प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना रहा, जिसमें समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकीय नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन जैसी प्राथमिकताएं प्रमुख रहीं। दूसरी ओर, चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता, और हिंद महासागर में सैन्य उपस्थिति के माध्यम से क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता रहा है। अमेरिका और भारत की बढ़ती निकटता ने चीन को सैन्य विस्तार, वैकल्पिक आर्थिक संस्थानों (जैसे AIIB, RCEP) और कूटनीतिक रणनीतियों के माध्यम से प्रतिक्रिया देने पर बाध्य किया है। इस त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा ने न केवल हिंद–प्रशांत क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक परिदृश्य को पुनर्परिभाषित किया है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, व्यापार मार्गों की स्थिरता और तकनीकी वर्चस्व की दिशा भी तय की है।

KEYWORD: *हिन्द प्रशान्त क्षेत्र, अमेरिका, भारत, क्वाड,*

चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को संतुलित करने के साझा प्रयासों ने दोनों लोकतंत्रों के बीच सहयोग को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचा दिया। आर्थिक, रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी का दायरा विस्तृत हुआ, जिसमें क्वाड एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच के रूप में उभरा। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में चीन की उपस्थिति को अमेरिका और भारत एक प्रकार की रणनीतिक चुनौती मानते हैं। अतः, विशेष रूप से बाइडन युग में, अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते सहयोग ने चीन को हिंद–प्रशांत में अपनी रणनीति पुनःपरिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य उपस्थिति और आक्रामक समुद्री दावों के प्रतिप्रश्नस्वरूप, भारत और अमेरिका ने नौवहन स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी साझेदारी और रणनीतिक संवाद को प्राथमिकता दी। यह उभरता हुआ रणनीतिक त्रिकोण आज वैश्विक शक्ति–संतुलन, व्यापारिक संरचना और सुरक्षा व्यवस्था के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, बाइडन प्रशासन के तहत अमेरिका–भारत साझेदारी का विश्लेषण करना न केवल हिंद–प्रशांत की स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति में चीन की बदलती भूमिका के अध्ययन के लिए भी अनिवार्य है।

अमेरिका, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संबंध

पिछले कुछ दशकों में अमेरिका, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं जिसमें भारत की भूमिका न केवल संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई है, बल्कि यह अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टकराव के बीच एक रणनीतिक धूरी बन चुका है।

शीत युद्ध के समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी लेकिन 21वीं सदी में, विशेषकर चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व की महत्वाकांक्षाओं के मद्देनजर, भारत ने अपनी विदेश नीति में व्यावहारिक पुनर्संरेखन किया है। इसका स्पष्ट संकेत 2005 में हुए भारत–अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते से मिलता है, जिसने दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग की नई राह खोली। इस साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए बाद में BECA और COMCASA जैसे समझौतों ने भारत की सैन्य क्षमताओं को तकनीकी और रणनीतिक रूप से सशक्त किया। BECA से जहां भू–स्थानिक खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा मिली, वहीं COMCASA ने सुरक्षित और सुसंगत संचार प्रणालियों की नींव रखी। इन समझौतों ने चीन को यह स्पष्ट संकेत दिया कि भारत अब केवल एक संतुलनकारी शक्ति नहीं, बल्कि अमेरिका समर्थित रणनीतिक गठबंधन का सक्रिय भागीदार है।

इस सैन्य सहयोग का ठोस उदाहरण मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, जो प्रारंभ में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय था, किंतु बाद में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों की भागीदारी ने इसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD) की सामरिक परिकल्पना से जोड़ दिया। इस अभ्यास ने भारत की नौसैनिक शक्ति, विशेषकर पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी और बहुराष्ट्रीय सुसंगतता के क्षेत्रों में, उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की। सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिका–भारत सहयोग त्रिपक्षीय

1: Corresponding Author

शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। "इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (ICET)" जैसे संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य 5G, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और अर्धचालक जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करना है। यह साझेदारी न केवल तकनीकी नवाचारों को गति देती है, बल्कि "मेड इन चाइना 2025" जैसी चीनी रणनीतियों के समक्ष चुनौती भी प्रस्तुत करती है। इन टकरावों ने भारत–चीन संबंधों में नई तरह की प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जहाँ प्रौद्योगिकी अब केवल आर्थिक विकास का नहीं, बल्कि सामरिक प्रभुत्व का भी साधन बन चुकी है। अमेरिका इस मोर्चे पर भारत के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा है और चीन की तकनीकों को लेकर जासूसी जैसी आशंकाओं के बीच भारत के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बन रहा है। बीजिंग इन घटनाक्रमों को गहरी चिंता के साथ देखता है। चीन को यह आशंका है कि अमेरिका भारत को रणनीतिक रूप से अपने पक्ष में खड़ा कर हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में उसे घेरने की कोशिश करता है। चीन की यह धारणा क्षेत्रीय तनाव और सैन्य होड़ को बढ़ावा दे सकती है, जिससे वह अपनी नौसैनिक उपस्थिति को और आक्रामक बनाए।

BRI बनाम FOIP: विरोधाभासी भू–सांस्कृतिक दृष्टिकोण–

भारत और अमेरिका के बीच गहराते रणनीतिक सहयोग ने इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति–संतुलन को पुनर्परिभाषित किया है, जिससे चीन के लिए गहरे भू–राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। अमेरिका द्वारा प्रतिपादित ''फ्री एंड ओपन इंडो–पैसिफिक'' रणनीति का प्रमुख उद्देश्य नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय स्थिरता और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के बढ़ते वर्चस्व को संतुलित करना है।

चीन की BRI नीति एक बहुआयामी कनेक्टिविटी मॉडल है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्र मार्गों से जोड़ने की परिकल्पना करती है। हालाँकि, इसमें पारदर्शिता की कमी, ऋण स्थिरता पर चिंताएँ और राजनीतिक अधिभावी रुझान जैसे कारकों ने कई देशों को सतर्क कर दिया है। इसके विपरीत, FOIP एक ऐसा वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है जो नियम–आधारित, सहभागी और संप्रभुता का सम्मान करने वाला है विशेषतः उन राष्ट्रों के लिए जो BRI के दीर्घकालिक प्रभावों से आशंकित हैं। FOIP की अवधारणा, जो पारदर्शिता, समावेशिता और नियम आधारित विश्व व्यवस्था की वकालत करती है, सीधे तौर पर BRI के उस मॉडल से टकराती है जिसे पश्चिमी विश्लेषकों ने अक्सर "ऋण–जाल कूटनीति" (Debt & Trap Diplomacy) की संज्ञा दी है। इस रणनीतिक ढांचे में भारत एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, विशेषतः लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय सुरक्षा में साझा हितों के आधार पर।

क्वाडः सामरिक पुनरुद्धार और चीन की चिंता–

इस त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा का सबसे स्पष्ट रूप क्वाड (Quad) के पुनर्जीवन में देखा जा सकता है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस चतुर्पक्षीय संवाद को चीन एक नव–गठित ''एशियाई नाटो'' के रूप में देखता है। 2007 में आरंभ हुआ यह मंच भले ही कुछ वर्षों के लिए निष्क्रिय रहा हो, किंतु 2017 के बाद इसकी सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियाँ उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं। क्वाड द्वारा आयोजित मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, रणनीतिक संवाद और अवसंरचना सहयोग की परियोजनाएँ चीन के लिए स्पष्ट संदेश हैं कि क्षेत्रीय शक्तियाँ उसके उदय के समांतर संतुलन बनाने का प्रयास कर रही हैं। विशेषकर गलवान घाटी में 2020 की झड़प के पश्चात चीन ने भारत की सैन्य तैनाती और क्वाड की गतिविधियों को लेकर असंतोष प्रकट किया है। बीजिंग इस गठबंधन को न केवल अपनी रणनीतिक गहराई में हस्तक्षेप मानता है, बल्कि यह उसे एशिया में एक बहुध्रुवीय व्यवस्था के विरुद्ध सामूहिक प्रतिक्रिया प्रतीत होती है।

चीन की रणनीतिक प्रतिक्रियारू विभाजन और वैकल्पिक नेटवर्क निर्माण–

क्वाड के उद्भव और थ्व्च् के प्रसार के प्रति चीन की प्रतिक्रिया केवल आलोचना तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसने वैकल्पिक कूटनीतिक एवं आर्थिक नेटवर्क खड़े करने का भी प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, चीन ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संवाद को तीव्र किया है ताकि क्वाड की एकता को कमजोर किया जा सके। दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के साथ भी चीन ने सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है — ASEAN के माध्यम से जिससे वह FOIP के प्रभाव को संतुलित कर सके।

इस रणनीति में चीन ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) को प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया है। AIIB, जिसकी स्थापना चीन ने 2016 में की थी, विश्व बैंक और IMF जैसी पश्चिम–प्रधान संस्थाओं के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं, RCEP के माध्यम से चीन ने एशिया–प्रशांत क्षेत्र में अपना आर्थिक नेतृत्व बनाए रखने की कोशिश की है।

चीन का समायोजनात्मक दृष्टिकोणः संयम और पुनः सन्तुलन–

हालांकि चीन ने FOIP और क्वाड को खुले तौर पर चुनौती दी है, फिर भी उसका दृष्टिकोण पूर्णतः टकरावकारी न होकर कभी–कभी समायोजनात्मक भी रहा है। चीन यह समझता है कि क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक निरंतरता उसके दीर्घकालिक हित में है। इसलिए, वह एक ओर जहाँ प्रतिस्पर्धी आर्थिक संस्थाओं और कूटनीतिक गठबंधनों का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह क्वाड सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखने का भी प्रयास करता है — ताकि संपूर्ण टकराव की स्थिति को टाला जा सके।

चीन, भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और इंडो–पैसिफिक क्षेत्ररू प्रतिक्रिया और पुनर्संयोजन–

वर्तमान में क्वाड एक प्रभावशाली बहुपक्षीय मंच के रूप में उभरा है, जो हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन की व्यापक रणनीतिक उपस्थिति को संतुलित करने के उद्देश्य से सक्रिय है। हालांकि चीन इस बहुपक्षीय संरचना को कमजोर करने हेतु द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासों, आर्थिक सौदों और क्षेत्रीय संस्थानों पर प्रभाव के माध्यम से कार्यरत है। इसके विपरीत, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और तकनीकी सहयोग BRI के लिए एक व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत कर रहा है, विशेषकर विकासशील देशों के लिए जो पारदर्शी और

टिकाऊ निवेश विकल्पों की तलाश में हैं। Blue Dot Network, Global Gateway, और G7 की Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) जैसे वैकल्पिक ढाँचागत पहलें इस प्रतिस्पर्धा को और अधिक तीव्र बना रही हैं।

अमेरिका–भारत सहयोग पर चीन की प्रतिक्रियाएं–

पिछले एक दशक में अमेरिका और भारत के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक मामलों में गहन सहयोग ने चीन को अपनी भूराजनैतिक रणनीतियों की पुनर्समीक्षा और सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय स्तरों पर बहुआयामी प्रतिक्रियाएं देने की ओर प्रेरित किया है। चीन की सबसे मुखर प्रतिक्रियाओं में से एक उसकी नौसैनिक शक्ति का तीव्र विकास है। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य आधार, रनवे और रडार प्रतिष्ठान विकसित कर उसने क्षेत्रीय प्रभुत्व की स्पष्ट घोषणा की है। साथ ही, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भी अपनी उपस्थिति सशक्त की है, जिससे वह भारत–अमेरिका नौसैनिक सहयोग–विशेषकर 'मुक्त नौवहन अधिकार' (freedom of navigation) की अवधारणा का प्रभावी प्रतिरोध कर सके।

भारत के साथ एलएसी (Line of Actual Control) पर भारत चीन का रुख अधिक आक्रामक हुआ है। जून 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद दोनों देशों द्वारा सीमा पर सैन्य तैनाती और बुनियादी ढांचे का तीव्र विस्तार हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में, पाकिस्तान के साथ चीन के संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत के लिए एक ''द्वि–मोर्चीय दबाव'' रणनीति के रूप में देखे जा सकते हैं। भारत–अमेरिका सहयोग को संतुलित करने हेतु चीन ने पाकिस्तान के साथ पारंपरिक रणनीतिक संबंधों के अतिरिक्त, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों में आर्थिक निवेश व कूटनीतिक सक्रियता के माध्यम से भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती देने का प्रयास किया है। BRI के अंतर्गत हम्बनटोटा बंदरगाह का लीज पर अधिग्रहण चीन की ''ऋण–जाल कूटनीति'' का उदाहरण है, जो उसे न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक लाभ भी प्रदान करता है। इसी तरह, नेपाल में बढ़ते चीनी निवेश को भारत चीन की हिमालयी घेरेबंदी की दृष्टि से देखता है।

Quad के स्वास्थ्य कूटनीति प्रयासों को संतुलित करने के लिए कोविड–19 वैश्विक संकट के समय चीन ने कई विकासशील देशों को शीघ्र वैक्सीन सहायता प्रदान कर स्वयं को एक ''जिम्मेदार वैश्विक शक्ति'' के रूप में प्रस्तुत किया। हालाँकि, वैक्सीन की प्रभावशीलता और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों ने चीन की छवि को कुछ हद तक प्रभावित भी किया।

चीन की आर्थिक रणनीति का मूल स्तंभ है उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और AIIB जैसे संस्थानों का उपयोग। भारत द्वारा BRI का विरोध, विशेषकर CPEC के कारण, इस परियोजना की संवेदनशीलता को उजागर करता है। किंतु चीन दक्षिण एशिया और अफ्रीका में इन परियोजनाओं के माध्यम से अपनी आर्थिक पकड़ बनाए रखे हुए है। AIIB का उपयोग चीन ने एक वैकल्पिक वित्तीय ढांचे के रूप में किया है जिससे वह IMF और विश्व बैंक के पश्चिमी प्रभुत्व को संतुलित करने की कोशिश करता है। भारत और अमेरिका के बीच उभरते तकनीकी गठबंधन–जैसे iCET (Initiative on Critical and Emerging Technologies) ने चीन को अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता पर बल देने को विवश किया है। तकनीकी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, चीन ने 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तीव्र गति से कार्य किया है। मेड इन चाइना 2025 जैसी पहलें इस प्रयास का केंद्र हैं, जिनका उद्देश्य पश्चिमी तकनीकी निर्भरता को समाप्त कर चीन को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है।

इस प्रकार, चीन की प्रतिक्रियाएँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि वह भारत और अमेरिका के बीच उभरती रणनीतिक निकटता को अपनी दीर्घकालिक भू–रणनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखता है। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में भारत–अमेरिका सहयोग की प्रकृति और तीव्रता ने चीन को न केवल सामरिक, बल्कि वैचारिक और तकनीकी स्तर पर भी अपनी रणनीतियाँ पुनः परिभाषित करने के लिए बाध्य किया है। इस संघर्ष का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार ये तीनों शक्तियाँकृभारत, अमेरिका और चीनकृ अपनी प्राथमिकताओं, गठबंधनों और तकनीकी नवाचारों को संतुलित करती हैं।

रणनीतिक संघर्ष : BRI बनाम CPEC और वैकल्पिक वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ–

भारत और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा का केंद्र केवल सीमा विवाद या कूटनीतिक मतभेद नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और वित्तीय संरचनाओं की दिशा तय करने की होड़ भी है। भारत–अमेरिका रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य न केवल BRI जैसी परियोजनाओं का विकल्प प्रस्तुत करना है, बल्कि दक्षिण एशिया को एक पारदर्शी, सतत और समावेशी विकास मॉडल की ओर उन्मुख करना भी है। CPEC को लेकर भारत का विरोध केवल संवैधानिक संप्रभुता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह बीआरआई के माध्यम से चीन द्वारा पाकिस्तान और श्रीलंका में गहराए गए रणनीतिक प्रभाव की प्रतिक्रिया भी है। भारत–अमेरिका द्वारा संयुक्त बुनियादी ढाँचा और तकनीकी परियोजनाएँ–जैसे क्वाड (Quad), IPEF, और क्लीन नेटवर्क इनिशिएटिव–दक्षिण एशिया में चीन पर रणनीतिक दबाव बनाती हैं। हालाँकि, BRI की भौगोलिक पहुँच, निवेश का पैमाना और क्रियान्वयन की तीव्रता ऐसी है कि भारत–अमेरिका गठजोड़ को इसके समकक्ष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि, वित्तीय प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय भागीदारों के विश्वास को सशक्त बनाना होगा।

भविष्य की चुनौतियाँ और संभावनाएँ–

21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में इंडो–पैसिफिक क्षेत्र को शक्ति संतुलन के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। यह भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल समुद्री सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीकी प्रभुत्व, व्यापारिक नेटवर्क, और राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव का भी क्षेत्र बनती जा रही है। ऐसे परिप्रेक्ष्य

में यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि यदि भारत और अमेरिका की साझेदारी दीर्घकालिक और संस्थागत स्वरूप धारण कर लेती है, तो चीन की ष्हेजेमोनिक रणनीतिष कृ विशेष रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया में कृ को लागू करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा।

हालांकि, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि चीन की विदेश नीति में अनुकूलन क्षमता अत्यंत सशक्त रही है। वह तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी रणनीतियों को पुनर्संयोजित करने और वैकल्पिक मार्गों की तलाश में दक्ष रहा है। इस दृष्टि से, भविष्य का अध्ययन इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि चीन इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी गठबंधनों और लोकतांत्रिक साझेदारियों के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रियात्मक ढांचा विकसित करता है–विशेष रूप से उन परिस्थितियों में, जहाँ पारदर्शिता, विधिशासन और समावेशिता की माँग बढ़ रही है। यदि चीन अपनी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को स्थिर बनाए रखना चाहता है, तो उसे भारत के साथ तनावों को कम करने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। ब्व्ब् को लेकर भारत की संप्रभुता संबंधी आपत्तियों को संज्ञान में लेना, स्।ब् पर विश्वास निर्माण के उपाय करना, और पारस्परिक हितों (जैसे कि जलवायु, स्वास्थ्य और व्यापार) में सहयोग बढ़ाने आदि माध्यमों से चीन क्षेत्रीय तनाव को नियंत्रित कर सकता है। साथ ही, चीन को अपने ठत् ढाँचे को अधिक पारदर्शी, सहभागी और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बनाना होगा, ताकि उसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिले। यह न केवल दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक दक्षिण में भी उसकी स्वीकार्यता को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष

भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी इंडो–पैसिफिक में चीन की वर्चस्ववादी नीतियों के प्रति एक संगठित उत्तर है। यह सहयोग केवल सामरिक प्रतिरोध नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक भू–अर्थव्यवस्था और वैश्विक शासन मॉडल का भी प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि चीन ने अपने गठबंधनों और BRI जैसे प्रयासों से अपना प्रभाव बढ़ाया है, परंतु वैश्विक परिदृश्य में पारदर्शिता, सततता और लोकतांत्रिक मूल्यों की माँग लगातार बढ़ रही हैकृजिसमें भारत–अमेरिका गठजोड़ की भूमिका निर्णायक बन सकती है। आने वाले वर्षों में भारत, अमेरिका और चीन के मध्य यह त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा न केवल इंडो–पैसिफिक की दिशा तय करेगी, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी नया आकार देगी।

REFERENCES

अधव, पी. (2023) *यू.एस.–भारत संबंध : अभिसरण और विचलन का मूल्यांकन,* यू.एस.–इण्डिया रिलेशन्स 1(12),1–33.

अफशारिपुर, ए. (2010), भारत के कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारों का वादा और चुनौतियाँ, *इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स,* 1(1), 33–70।

अहमद, एम. (2021), *विश्वास का मामला : ट्रूमैन से ट्रम्प तक भारत–अमेरिका संबंध,* हार्पर कॉलिन्स,नई दिल्ली,

अली, एस.एम. (2020), केस स्टडी 2: इक्कीसवीं सदी का समुद्री रेशम मार्ग, चीन का बेल्ट एंड रोड विजन, 231–289

अनवर, और डेवी फोर्टुना (2023), *इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में चीन के उदय और अमेरिका–चीन के पुनरुत्थान के चरण में इंडोनेशिया हेजिंग प्लस नीति,* एच.एफ. काई हे (एड), नेविगेटिंग इंटरनेशनल ऑर्डर ट्रांजिशन इन द इंडोपैसिफिक (पृष्ठ 125–151) लंदन।

अजीज, एस. एन., और बसीर, एस. एम. (2022), दक्षिण चीन सागर *जर्नल ऑफ टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम स्टडीज,* **9(2),** 65–82।

बीसन, एम., और जू, एस. (2019)– *वैश्विक शासन में चीन की उभरती भूमिका:* एआईआईबी और वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सीमाएँ, के. एच. झांग में, वैश्विक शासन में चीन की उभरती भूमिका (पृष्ठ 345–360)।

चेल्टेनहैम, यूकेः एडवर्ड एल्गर पब्लिशिंग भारती, एम. एस. (2023)।*भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी और कैसे चीन का प्रभाव इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में भारत–अमेरिका गठबंधन को चुनौती देता है* क्षेत्रीय गठन और विकास अध्ययन, 16–26।

हुसैन, एस. (2024). चीन के उदय का डर और चिंताः इंडो–पैसिफिक की प्रतिक्रिया को समझना, *जर्नल ऑफ इंडो–पैसिफिक अफेयर्स,* 321–342.

हुसैन, एफ., अहमद, डी.एम., नवाज, एस., हैदर, एस.ए., और आतिफ, एम. (2021). *चीन–पाक आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के लिए चुनौतियाँः भारतीय परिप्रेक्ष्य,* प्राथमिक शिक्षा ऑनलाइन, 3764–3770.

ह्वांग. (2020). चीन के 5जी उद्योग पर अमेरिका–चीन विवादों का प्रभाव हुआवेई मामले पर केंद्रित है, *जर्नल ऑफ कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,* **24(3)**, 420–427.

जाबीन, एम., और अहमद, आई. (2011). भारत–अमेरिका परमाणु सहयोग, *साउथ एशियन स्टडीज,* **26(02)**, 411–429.

काकर, एस. ए. (2022).चीन को नियंत्रित करनाः भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग. *बीटीटीएन जर्नल,* **01(01)**, 68–84